

रजिस्ट्रेशन नं० HP/13/SML/2004



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 26 अक्टूबर, 2004/4 कार्तिक, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 26 अक्टूबर, 2004

संख्या एल0एल0प्रार0डी0(6)18/2004-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25-10-2004 को

2337-राजपत्र/2004-26-10-2004 - 1,487.

(2207)

मूल्य : एक रुपया।

प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

2004 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2004

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद, 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2004 है ।

संक्षिप्त
नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

धारा 42 का
प्रतिस्थापन ।

“42. फीसों में वृद्धि करने, कमी करने, परिहार करने या प्रतिदाय करने की शक्ति.—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में उपबन्धित या अधिनियम से संलग्न प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त फीसों में या उनमें से किसी में वृद्धि कर सकेगी, कमी कर सकेगी, परिहार कर सकेगी या प्रतिदाय कर सकेगी और उसी रीति में ऐसी अधिसूचना को विखण्डित या संशोधित कर सकेगी ।” ।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

शिमला :
तारीख :

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Himachal Pradesh Ordinance No. 4 of 2004.

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT)

ORDINANCE, 2004

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth year of the Republic of India.

AN

ORDINANCE

further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968)

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

- | | |
|-----------------------------|---|
| Short title. | 1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2004. |
| Substitution of section 42. | 2. For section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, the following shall be substituted, namely :—
“42. <i>Power to enhance, reduce, remit or refund fees.</i> —The State Government may, by notification in the Official Gazette enhance, reduce, remit or refund, all or any of the fees provided in this Act or specified in the First and Second Schedule appended to the Act, and may in the like manner rescind or amend such notification.”. |

VISHNU SADASHIV KOKJE,

Governor.

Himachal Pradesh.

Place.....

Date.....

Sd/-
Secretary (Law),
Himachal Pradesh.